

00000000 000000

जनसत्ता 27 जून, 2014 : देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मगर परिवर्तन का आश्वासन देने वाले उसकी कतस्वीर अपने मन में बना लेते हैं और उसे मनचाहे ढंग से परोसते रहते हैं। परिवर्तन का आश्वासन कई बार घोषित। नचाने की तरह होता है। जब तक वह नाचता है, तब तक साईंस के लगता है कि घोषित। उसके इशारे पर चल रहा है। नाच देखने वाले भी आनंद लेते रहते हैं। जहां घोषित। अलफिहुआ, साईंस तो तरबतर होता ही है, तमाशबीन भी ततिर-बतिर हो जाते हैं। मोदीजी परिवर्तन और वक्स के घोषित के नचाते हु। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो ग। यह देश के ली भी ब। अनुभव है। यह सरकार न। अंदाज के साथ आई है।

अभी प्रधानमंत्री ने भूटान यात्रा की। वहां से लौट कर उन्होंने कहा कि वह उनके ली यादगार यात्रा है। ऐसे उनके सैक। यात्रा। होंगी। यह पहला अवसर था जब उन्होंने किसी देश की संयुक्त संसद के संबोधित किया। वहां की परंपरा के विपरीत अपने भाषण पर सांसदों से तालियां बजवा लीं। वहां तालियां बुरी आत्माओं के भगाने के ली बजाई जाती है, लेकिन सांसदों ने अपनी बुरी परंपरा के कविश्वव्यापी परंपरा में बदल कर अच्छी परंपरा बना दिया। आशा है, वे इस परंपरा के आगे भी चालू रखेंगे।

इसी दौरान दो बातें हुईं। कतो प्रधानमंत्री का यह कहना कि हदुस्तान का मजबूत होना छोटे देशों की सुरक्षा के ली आवश्यक है। यह बात मेरे कनों के उसी तरह अखरी जैसे चैनलों पर आने वाले कर के कविज्ञापन में पीछे बैठा पति पुत्र से पूछता है कि क्वीलरेटर पर पांव पडुं च रहा है या नहीं। वह उसे नागवार गुजरता है। जब वह ड्राइवर की सीट पर बैठा कर चला रहा है तो दूसरा व्यक्ति, भले वह उससे ब। हो, उसे कद में अपने से छोटा होने का अहसास कैसे करा सकता है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के शासन तक प।सी देश इस बात से बहुत नाराज थे कि हदुस्तान का व्यवहार उनके साथ बगि बर्दर जैसा है। कोई छोटा देश हो या ब।, सबका कद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान है। नेहरू के संदर्भ में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्ण ने इस बात का संकेत भी दिया था। मोदीजी ने उन्हें छोटा देश कह कर आहत तो नहीं किया? जब ब। देशों में हमें गरीब देश कहा जाता है तो अच्छा नहीं लगता। बताते हैं कि कबार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले समय नक्सन ने इंदिराजी के वाशिगटन आने के ली नमिंटरण दिया, तो उन्होंने उसे यह कह कर टाल दिया था कि यह मेरे जेंडे पर नहीं है। इस तरह के व्यवहार से प।सी देश नाराज होते हैं।

दूसरी बात हमारे रक्षामंत्री की सरहद दौरे से संबंधित है। वे नयिंटरण रेखा का नरीक्षण करने ग। थे। युद्धपोत वकिमादतिय के देश के समरपति करने के सलिसल्लि में मीडिया ने प्रधानमंत्री के सागर पोत का कमांडर बताया था, उसी दिन रक्षामंत्री नयिंटरण रेखा के दौरे पर ग। थे। वहां जाकर उन्होंने सेना के प्रबंधन के प्रति अपनी संतुष्टि प्रकट की। इससे जरूर सेना का मनोबल ब। होगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बातचीत के जरा। समस्याओं का हल निकलने के आश्वासन के बरक्स रक्षामंत्री ने कहा कि जब तक आतंकी हमले नहीं रोके जा।गे, तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। यह बात प्रधानमंत्री के आश्वासन के उलट है।

हालांकि उनके इस वक्तव्य के बाद 17 जून के कुछ अखबारों में छपा है कि पाकिस्तान और हदुस्तान की व्यावसायिक मुद्दों पर सचिव स्तर की जल्दी बात होगी। रक्षामंत्री ही वतित्तमंत्री भी हैं। व्यावसायिक मुद्दों पर बातचीत वतित्त मंत्रालय के अधीन होगी। लगता है कि वतित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की बात अलग-अलग क्णों से कही गई है। व्यक्ति। कहो सकता है, पर मंत्रालयों का नजरिया अलग हो जाता है। इस बार मोदीजी ने मंत्रालय के बंटवारे में प्रयोग कि है। यह उनका विशेषाधिकार है। उस पर प्रश्नचिह्न लगाना ठीक नहीं, मगर चर्चा हो सकती है।

कई समस्या सामने आ गईं। सबसे पहली गांठ तो केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री नहिलाल चंद के ऊपर लगे बलात्कार के आरोप की है। मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर अपना उत्तर देते हुए दागी सांसदों के बारे में कहा था कि कसाल के अंदर लंबित मुकदमे तय किए जाएं, जो नरिदोष हों वे बने रहें, जो दागी साबित हों जेल जाएं।

इस बात से लोगों को लगा था मोदी संसद में दां ग आश्वासन पर जरूर अमल करेंगे। पर रसायनमंत्री ने गांी अटक दी। राजस्थान के भाजपा सरकार के मंत्री राठी साहब उन्हें नरिदोष बता रहे हैं। अब तो पूरी पार्टी समर्थन में आ गई है। पीति महिला ने अपने सम्मान की बाजी लगा कर पुनर्विचार याचिका दायर की है। क्या वह झूठ बोल रही है? अगर बोल भी रही है तो पार्टी मोदीजी के संसद में दां ग आश्वासन का सम्मान तो करे।

रसायनमंत्री संसद का टिकट पाते समय कथित दागी रहे होंगे। जहां इतने तथाकथित अन्य दागी प्रत्याशियों को टिकट मिले, वहां उनके भी मिल गया। पर मंत्री को समन मलिना, वह भी बलात्कार के मामले में, नाजुक बात है। प्रधानमंत्री चुप हैं। भाजपा उन्हें बने रहने के लिए कह रही है। आधी आबादी के सम्मान का सवाल है। वे उन्हें कह सकते हैं कि फलिहाल त्यागपत्र दे दो, जब पाक-साफ होकर आओगे तो हम राज्यमंत्री तो क्या, पूरा मंत्री बना देंगे। महिलाओं को इस बात से सम्मान भी मिलेगा और आश्वासन भी, कि प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान के प्रति गंभीर हैं। वरना सरकारों का स्थायी जवाब होता है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यही भाजपा कह रही है। खैर, यह नरिणय तो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दूसरा संकट महंगाई का है। प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी महंगाई के सवाल से जूझ रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा इसी बात को लेकर दिया गया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कह रही हैं कि पता नहीं अच्छे दिनों के लिए कतिना इंतजार करना पड़े। अच्छे या बुरे दिन सरकारों के हाथ में नहीं होते। उसके लिए बहुत से तत्त्व जम्मेदार होते हैं। कांग्रेस के बुरे दिन मोदी के अच्छे दिन में बदल गए। जनता के दिन वर्तमान हालात में बुरे दिन ही न होकर रह जायें। चैनलों ने तो अभी से नारे में अच्छे दिन शब्द को काट कर महंगे दिन का दिया।

इराक का शिया-सुन्नी झगड़ा और सुन्नियों का इतना आक्रामक होते जाना कि हुकूमत को नषिक्रिय बना कर देश के बहुत बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर लेना, दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति बदल रहा है। इराक पेट्रोल का बड़ा पूरतकिर्ता देश है। हदुस्तान के लिए दूसरे नंबर का पूरतकिर्ता है। वहां के सबसे बड़े शोधक करखाने के पचहत्तर प्रतिशत हिस्से पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो हदुस्तान में महंगाई बढ़ेगी। दूसरी समस्या चालीस भारतीयों के अगवा करके अज्ञात स्थान पर रखा गया है। टीवी चैनल रात-दिन दिखा रहे हैं कि उनके संबंधी रो-रोकर बेहाल हैं। उनका वापस आना देश की शांति से जुड़ा है।

शिया-सुन्नी का मतांतर लखनऊ के दोनों वर्गों को प्रभावित कर रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है कि वह हर केशशि कर रही है उन्हें सही-सलामत वापस लाने की। अभी तक पता नहीं कि वे कहां रखे गए हैं। पता भी चल गया तो क्या करेंगे। यही नहीं, तीस छात्र भी फंसे हैं। दरअसल, चालीस लोग अगवा कर लिए गए तो दबाव बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन जो लगभग अठारह हजार लोग वहां से आना चाहते हैं उन्हें लाने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।

सरकार हर क्षेत्र में सबसिडी वापस लेने की बात कह रही है। रेलमंत्री ने रेल करिया 14.2 प्रतिशत बढ़ा दिया। उनका कहना है कि पहली सरकार का प्रस्ताव था, उसे लागू किया गया है। यह सरकार अगर पहली सरकार के मसूबों को बना नुक्ता हटा करियान्वित कर रही है, तो फिर नई सरकार की मौलिकता कहां रही। वैसे पहली सरकार ने कभी इतना करिया नहीं बढ़ाया। यह सरकार तो उनके प्रस्ताव में दो प्रतिशत भी कम करने के तैयार नहीं हुई। ये सब

स्थलितियां अचछे दनि लाने में उकवट पैदा कर सकती है।

इस बीच मुसलमि देशों के साथ हमारे पहले जैसे संबंध नहीं है। नहीं तो मतिर मुसलमि देशों के माध्यम से वहां फंसे लोगों के वापस लाने की केशशि की जा सकती थी। मोदीजी के बारे में माना जाता है वे मंसूबों के व्यावहारिकिजामा पहनाने में माहरि है, पर जब बात दूसरे देशों की हो तो वह महारत कतिनी कमयाब होगी, कहना मुश्कलि है।

मैने गृहमंत्री के व्यक्तगित सचवि की नयिक्तिकि मामला फेसबुकपर डाला था। कसिी सजजन ने, जो संभवतः मोदी-भक्त है, लिखा कि करदों के साथ यही होता है। अब तो कर्मकिमंत्रालय से आदेश जारी हो गया कि कोई मंत्री पहली सरकर के मंत्रियों के साथ रहे कर्मियों में से कसिी के अपने यहां नहीं रखेगा, सब नरिणय प्रधानमंत्री करेंगे। राज्यपालों पर तो गाज गरि ही रही है, छोटे अफसर और बाबू लोग नफरत के लपेटे में आ जाँगे, यह उम्मीद नहीं थी।

सुना है, गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपनी व्यथा कही है। कनूनमंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने वक्तव्य दिया कि हर मंत्री के अपने नरिणय लेने का अधिकार है। उपरोक्त आदेश के बाद न गृहमंत्री की व्यथा का मतलब है, न कनूनमंत्री के वक्तव्य का। ये सब बातें नई सरकर के संचालन में कहां तक सहायक हो सकती है, कहना मुश्कलि है। सवाल इस बात से भी जुड़ा है कि प्रधानमंत्री ने यूपी का कर्यकल के कैबिनेट सचवि के छह महीने का सेवा वसितार दे दिया, जबकि पहली सरकर उन्हें दो साल का वसितार दे चुकी थी। इससे पता चलता है कि वे उस सरकर के कतिने नबिठ थे। यह नीतियों के दोहरेपन की तरफ इशारा करता है। इतने ऊंचे स्तर पर तो और भी अधिक प्रधानमंत्री का घेरा नाचेगा, तो क्या मंत्रियों के टट्टुओं पर संतोष करना पड़ेगा!

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>